

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 4725/15-1

दिनांक, झांसी, जून, 05-2023

सेवा में,

✓ उप प्रबन्धक

अदानी टोटल गैस लि०,
झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषय:- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि०, झांसी द्वारा 200 एमएम डाया कार्बन स्टील पाइप लाइन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-27 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-44 के किमी० सं० 6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लॉक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- सचिव उ०प्र० शासन का पत्रांक-214/81-2-2023-800(340)/2022 दिनांक 19.05.2023 तथा प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/143751/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र को संलग्न कर अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० 29 के अनुसार प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 0.636 हे० वनभूमि की एन०पी०वी० की आगणित धनराशि 609148.00 (मु० छः लाख नौ हजार एक सौ अड़तालीस रु० मात्र) एवं शर्त सं० 31 के अनुसार 0.12 हे० वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित की आगणित धनराशि 746946.00 (मु० सात लाख छियालीस हजार नौ सौ छियालीस रु० मात्र) इस प्रकार शर्त सं० 29 व 31 की कुल धनराशि 609148.00+746946.00 = 1356094.00 (मु० तेरह लाख छप्पन हजार चौरानवे रु० मात्र) कैम्पा नई दिल्ली के खाते में ई-पोर्टल से प्राप्त चालान के माध्यम से जमा कर जमा रसीद की पांच (रंगीन फोटोकॉपी) एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या/वचनवद्धता अभिलेख 05-05 प्रतियों में शील व हस्ताक्षर सहित शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या

/अ/समादिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी



प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 19 मई 2023

विषय- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि० झांसी द्वारा 200 एमएम डायम कार्बन स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के किमी० संख्या-6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाइन/143751/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1278/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाइन/143751/2021 दिनांक 07.10.2022 एवं पत्र संख्या-2347/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाइन/143751/2021 दिनांक 16.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि० झांसी द्वारा 200 एमएम डायम कार्बन स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के किमी० संख्या-6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife

12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh.nic.in/).
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	गैस पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कंपैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
20	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
22	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-III(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
23	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shps/shape) फाइल में दर्शाया गया हो।
24	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
25	नोडल अधिकारी, डीओ द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
26	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाuna के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
27	प्रत्यापित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
28	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
29	प्रस्तावक विभाग द्वारा आओ उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईओ एओ संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसीओ, दिनांक 05-02-2009 के तहत भारत सरकार के पत्र दिनांक 06-01-2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19-01-2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनओपीओ एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण विधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

30	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
31	प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में के साथ DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात कार्यानुमति (Working Permission) विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।
33	प्रशंगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी भवदीय,

Date: 18-05-2023 17:59:47

Reason: Approved (आशीष तिवारी)
सचिवसंख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी।
- (3)- जिलाधिकारी, झांसी।
- (4)- प्रभागीय वनाधिकारी झांसी वन प्रभाग झांसी।
- (5)- उप प्रबन्धक अदानी टोटल गैस लि० झांसी।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3787 / 11-सी-FP/UP/Pipeline/143751/2021, लखनऊ, दिनांक: मई 31, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.08.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लेखन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- उप प्रबन्धक, अदानी टोटल गैस लि०, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।